भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2788**
**जिसका उत्तर शुक्रवार 19 मार्च, 2021 को दिया जाएगा**

## आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

**2788 #श्री वाइको: श्री सतीश चंद्र दुबे: श्री नीरज डांगी:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बढ़ती हुई महंगाई के कारणों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार है, यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक किया जाएगा;
(ख) यदि नहीं, तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ग) आम आदमी की सहायता हेतु महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और
(घ) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से आर्थिक और अन्य उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)**

(क) से (घ): सरकार, देश भर में स्थित 135 मूल्य निगरानी केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के कीमतों की निगरानी करती है। इन मूल्य रूझानों का विश्लेषण, वास्तविक समय के आधार पर एक अंतर - मंत्रालयी समिति द्वारा किया जाता है जो नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए उचित सिफारिशें करती है।

सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे कदमों के माध्यम से आयात शुल्क और निर्यात पर प्रतिबंध जैसे व्यापार और राजकोषीय नीति संबंधी कदमों का उचित ढंग से उपयोग करना शामिल है ताकि घरेलू उपलब्धता विनियमित की जा सके और कीमतों में नरमी लाई जा सके, स्टॉक सीमा अधिरोपित की जा सके और राज्यों को जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध कारगर कार्रवाई करने का सुझाव दिया जा सके और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जा सके। सरकार ऐसी स्कीमें भी लागू कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समुचित हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बफर से स्टॉक रिलीज कर दालों और प्याज जैसी कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण का कार्यान्वयन भी कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की मूल्य श्रृंखला के समेकित विकास के लिए "ऑपरेशन ग्रीन्स" नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, टी.ओ.पी. समूहों में उत्पादन योजना के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और किस्मों के दोहरे प्रयोग की शुरुआत करना है।

*******